



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

125-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 17, 2015 (ASADHA 26, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/01-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)– हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू) दिनांक 24 अगस्त, 2012 को विखण्डित करते हैं।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th July, 2015

No. 9/106/2001-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), Governor of Haryana hereby rescinds the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), the dated 24th August, 2012.

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार
लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)

अधिसूचना
दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/01-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)— हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उदग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू) दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 09/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू) दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, में, अनुसूची-1 में, खाना 2 तथा 3 के नीचे क्रम संख्या 17 तथा 25 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th July, 2015

No. 9/106/01-3B&R(W).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Schedule –I of the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch) Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), dated the 12th October, 2011, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W) dated the 12th October, 2011 in Schedule-I, under columns 2 and 3, against serial number 17 and 25 existing entries shall be omitted.

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार
लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)
अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/01-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)— हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उदग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू) दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 की अनुसूची-1 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 09/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू) दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, में, अनुसूची-1 में, खाना 2 तथा 3 के नीचे तथा क्रम संख्या 8 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों को 4 अगस्त, 2015 (24.00 बजे अर्थात् 4 और 5 अगस्त की मध्यरात्रि) से लोप किया जाएगा।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT**PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)****Notification**

The 17th July, 2015

No. 9/106/01-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule I of the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), dated the 12th October, 2011, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), dated the 12th October, 2011 in Schedule I, under column 2 and 3, against serial number 8 existing entries shall be omitted with effect from 4th August, 2015 (24:00 Hrs i.e. midnight between 4th and 5th August).

HARDEEP KUMAR,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)- हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)-(टोल-20) दिनांक 11 अगस्त, 2010 को 15 जुलाई, 2016 (15 जुलाई और 16 जुलाई के बीच मध्यरात्रि 24.00 बजे) से विखण्डित करते हैं।

हरदीप कुमार,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT**PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)****Notification**

The 17th July, 2015

No. 9/106/2001-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby rescinds the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(Works) (Toll-20), dated the 11th August, 2010 with effect from 15th July, 2016 (24:00 Hrs midnight between 15th July and 16th July).

HARDEEP KUMAR,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)— हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उदग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा), अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) अधिसूचना संख्या 09/106/2001-3बी० एण्ड आर० दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 में, अनुसूची-I में, खाना 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों को 31 अक्टूबर, 2015 (24:00 बजे अर्थात् 31 अक्टूबर तथा प्रथम नवम्बर की मध्यात्रि) से लोप किया जाएगा।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th July, 2015

No. 9/106/2001-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R, dated the 4th October, 2010, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), dated the 4th October, 2010 in Schedule I, under column 2, 3 and 4 against serial number 4 the existing entries shall be omitted with effect from the 31st October, 2015 (24:00 Hrs i.e. midnight between 31st October and 1st November).

HARDEEP KUMAR,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार
लोक निर्माण विभाग
(भवन तथा सड़कें शाखा)
अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)— हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उदग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) अधिसूचना संख्या 9/106/2001-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)— दिनांक 11 मार्च, 2015 को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करते हैं।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा)।

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th July, 2015

No. 9/106/2001-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby rescinds the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), Notification No. 9/106/2001-3B&R(W), dated the 11th March, 2015, with immediate effect.

HARDEEP KUMAR,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार
 लोक निर्माण विभाग
 (भवन तथा सड़कें शाखा)
 अधिसूचना
 दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 9/106/01-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)- हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उदग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें भाखा) अधिसूचना संख्या 9/106/01-3बी० एण्ड आर० (डब्ल्यू)-दिनांक 11 मार्च, 2015 को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करते हैं।

हरदीप कुमार,
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें भाखा)

HARYANA GOVERNMENT
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS BRANCH)

Notification

The 17th July, 2015

No. 9/106/01-3B&R(W)- In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (Act 9 of 1996), the Governor of Haryana hereby rescinds the Haryana Government, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), notification no. 9/106/01-3B&R(W), dated the 11th March 2015, with immediate effect.

HARDEEP KUMAR,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Public Works Department (Buildings and Roads Branch).

हरियाणा सरकार
 विकास तथा पंचायत विभाग
 शुद्धि पत्र
 दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या ई०सी०५०५-२०१५/५९१- हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग आदेश संख्या ई०सी०५०५-२०१५/५०९ में, पृष्ठ संख्या 1098 पर ग्राम पंचायत छप्परा खेड़ा खण्ड करनाल के समुख खाना नं० 9 में अंक 3 के स्थान पर अंक 4 पढ़ा जाये।

नवराज सन्धु,
 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

e-Auction Notice

The 17th July, 2015

DMG/HY/e-Auction/MGR/Bhi/2015/7059

It is hereby notified for the information of the General Public that mining leases for extraction of minor mineral "Stone along with Associated minor minerals" from mines of the districts of **Mahendergarh and Bhiwani** will be granted through the process of **e-Auction**. It is informed to all concerned persons/parties that who are otherwise not specifically debarred or are not defaulter on account of Government dues as per condition No. 6 of this notice **can participate in the e-Auction**. The e-Auction will be held on 11.08.2015 and bids can be submitted from **11.08.2015 at 09:00 AM to 12.08.2015 till 12.00 noon, extendable maximum up to 04:00 PM**. The important instructions for participation in the online e-Auction are as under:

- A. The bids shall be made online on the **e-procurement** website <https://haryanaeprocurement.gov.in>.
- B. The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create **their user account online by selection the option of e-auction from discipline column and obtain user-id / password** on the website <https://haryanaeprocurement.gov.in> (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-Auction of mines, please visit the aforementioned website and click on the available link "**How to...**" at the Home Page.
- C. After getting the *user account created*, the prospective/ intending bidders shall **upload** following **documents (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document)** along with deposition of **earnest money (EMD)** and **e-service fee** in order to participate in the e-Auction **by 07.08.2015** upto 05:00 PM anytime after the publication of this document:
 - (i) **"No Dues Certificate"** from the authorised officer or an affidavit sworn before any Magistrate to the effect that no amount of lease money, royalty, dead rent or surface rent is due in respect of any mining lease/mining lease or mineral concession held by him earlier or in respect of any mineral concession currently held by him or his family members;
 - (ii) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of company)**, or an affidavit (in case of sole proprietor); No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;
 - (iii) A copy of **authority letter** by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of the Board of Directors (BoD) of the Company in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency;
 - (iv) **Earnest Money** equal to 10% of the reserve price of the mining lease area for which bid has to be made, rounded by an amount of Rs.10,000/-, through online payment in due course of time i.e. up to 07.08.2015 till 05:00 PM. In case the intended bidder fails to pay online EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-Auction of mine(s). The payment for EMD fee can be made by eligible bidders online through RTGS / NEFT or OTC. (Please refer to important Payment Guidelines under Annexure – 'A' provided by online payment gateway service provider i.e. ICICI Bank).

The payment shall be made against the beneficiary account number as mentioned in the challan to be generated online at the **e-Procurement portal** <https://haryanaeprocurement.gov.in>.
 - (v) Details of the bidding agency in case of requirement of **refund of EMD** (a) Refund Account Name (b) Refund Account No. (c) IFSC code of the Bank. Note: Please cross check the information to be submitted online before saving the same as the information in non editable.
 - (vi) The Bidders shall have to pay **e-Service Fee of Rs.1000/- online** by using the service of secure electronic payment gateway. The secure electronic payments gateway is an online interface between leaseors and online payment authorization networks. The Payment for **e-Service Fee** can be made by eligible bidders/ leaseors online directly through **Debit Cards & Internet Banking Accounts**.
- Note:** Any document uploaded as per (i) , (ii) and (iii) above at later stage/ after auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

D. In case of any query regarding process of **e-Auction**, the intended bidder can contact the service provider at below mentioned address:

M/s Nextenders (India) Pvt. Ltd. O/o. Director Supplies and Disposal Haryana, SCO – 09, IIInd Floor, Sector –16, Panchkula – 134108 E - mail: Chandigarh@nextenders.com Help Desk: +91-172-2582008-09, 2618292 and **1800-180-2097** (Toll Free Number)

Note- A training-cum-orientation programme for the intending bidders will be held on **25.07.2015** and **01.08.2015** at Chandigarh office of **M/s Nextenders (India) Pvt. Ltd.** from 12:00 noon to 1:00 P.M. Parties interested in attending the same are requested to contact/confirm participation to Sh. Kanwarjeet Singh Mobile 09592259876, Sh. Sat Dev Sharma 9872252144 Sh. Deepak Mobile – 9501176347 or the helpdesk on Toll Free No. 1800-180-2097 and 0172-2582008/2582009/2618292 or through E-mail: chandigarh@nextenders.com.

E. Any bidder interested to participate in the auction can submit his bid/s from **11.08.2015 from 09:00 AM to 12.08.2015 till 12:00 noon**.

F. However, in case any bid in respect of any mine/ block is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12:00 Noon then the time for closure of the auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any of the mine, otherwise the same would get concluded.

G. In case the bidding would continue during such extensions of 10-10 minutes, the bidding process will finally conclude at 04:00 pm and no further extension would be given thereafter.

H. The minimum bid incremental value during the initial time provided i.e. up to 12.08.2015 till 12:00 noon will be multiple of Rs. 50,000 (Fifty thousand). However the increment during extended period (12.08.2015 from 12:00 noon till 04:00 PM) will be multiple of 100000 (one lakh) instead of 50,000 (Fifty Thousand).

The details of the areas of the Mines along with reserve price and period of mining leases which are to be granted on leases and other terms and conditions of the auction are given below:

Sr. No.	Name of the Mining Lease	Name of village	Khasra No. of mining lease area	Area in hectare	Reserve Price (Rs. in crore) per annum	Period of lease (in years)
Mahendergarh						
1.	Bakhrija Plot-3	Bakhrija	77 min,78 min, 79 min,80 min,81 min, 86 min, 87 and 88	40.62	47.55	12
2.	Bakhrija Plot-4		89 min, 90,91,92,93, 101 min,102 min and 103	34.64	40.55	12
3.	Usmapur	Usmapur	46 min	33.10	38.75	10
4.	Karota	Karota	61 min	9.55	11.20	10
Bhiwani						
5.	Kheribattar Plot No. 1		136	7.47	8.75	10
6.	Kheribattar Plot No. 2		139,140,141 min	42.01	49.15	12

7.	Pichopa Kalan Plot No. 2	Pichopa Kalan	110 min	22.40	26.20	10
8.	Pichopa Kalan Plot No. 3		109 min 110 min	11.00	12.90	10
9.	Kalyana Plot No. 2	Kalyana	216	29.50	34.55	12
10.	Asawari	Asawari	143	7.60	8.90	10
11.	Jhoju Kalan	Jhoju Kalan	305 min	6.00	7.05	10
12.	Manakawas Plot No. 1	Manakawas	176 & 177	20.34	23.80	10
13.	Manakawas Plot No. 2		167 min & 170	22.90	26.80	12

The terms and conditions of the Auction:

1. The period of lease shall commence w.e.f the date of grant of environmental clearance by competent authority as required under EIA notification dated 14.09.2006 and as amended from time to time by the MoEF, GoI or on expiry of a period of 12 months from the date of acceptance of highest bid/issuance of “**Letter of Intent**”,(LoI) whichever is earlier;
2. Any site/lease area can be withdrawn from the Auction without assigning any reason;
3. Due care had been taken in specifying the details of the areas of the mining lease. However, in case of any inadvertent clerical mistake, the same shall be got rectified/corrected even after the auction but before execution of lease deed;
4. The lease areas are **Tentative** and are being notified on ‘**as is where is basis**’ and all prospective bidders are expected and presumed to have surveyed the areas to make their own assessment for the potential of the areas for which bids are to be offered. The State Government shall not be responsible for any kind of loss in land / area or any other loss to the bidders/lessees at any point of time (before or after grant of lease) on account of reduction of land/ area or otherwise. Further, the bidders are also expected to have gone through the terms and conditions of auction notice and also the applicable Acts and Rules for undertaking mining;
5. No request regarding reduction in bid amount on account of reduction in land/area of the Mining lease, on any account including that of change in description of khasra numbers / location etc. at any stage will be entertained on any ground. This shall also include any loss/reduction of area for actual mining for want of compliance of applicable laws/restrictions for mining or part of the leased area had already been operated in the past. Needless to state that this also includes the changes, if any, as per condition No. (3) and the prospective bidder shall give their bids taking account of all such eventualities;
6. No person shall be eligible to participate in the Auction, who or any of his family members is a defaulter of any mining dues in respect of any mineral concession granted in the past or any other current mineral concession. In case any of the partners of a Partnership Firm or a Director of a company participating in the auction process or any of their family members are found to be defaulter, the bidder firm/company would be held ineligible;

Further, any person firm or company as the case may be who had been specifically debarred to participate in the auction would not be eligible to participate in the auction.

7. In case any bidder participated in the auction is found to be in arrears at any stage, his bid shall be revoked / cancelled with forfeiture of the amount deposited by him;
8. All intended participant can view the highest quoted bid during online bidding process. The highest bidder will be informed for confirmation of the same through **e-mail** and **SMS alert** at his online registered email and Mobile Number respectively;

9. The highest bid received shall become the '**annual dead rent**' amount payable by the bidder/lessee. The amount of annual dead rent initially determined on the basis of competitive bids/auctions shall be increased by 25% on completion of each block of three years;

Explanation: If the initially determined annually bid/lease Rs. 100/-, it shall be increased to Rs. 125/- with the commencement of the fourth year and to Rs. 156.25 with the commencement of the 7th year and so on and so forth for the next each block of three years.

10. The highest bidder would be informed about the same- confirmation that he being declared as **highest bidder**- as per which he shall be liable to deposit **25%** of the annual bid/dead rent as "**security**" and **one month's advance dead rent**. The above said amount shall be deposited as per following schedule:

- (a) an amount equal to 10% of the annual dead rent/ highest bid, after adjusting the EMD deposited for said mine, as 'initial bid security' within 24 hours of conclusion of the bidding process. The payment has to be made through RTGS/NEFT by secured online payment gateway ;
- (b) balance amount of bid security i.e. 15% of the annual dead rent along with one month's advance dead rent before commencement of the mining operation or before expiry of the period of 12 months, which ever is earlier;

11. In case the highest bidder fails to deposit 10% of the annual dead rent/bid amount online towards the "Initial bid Security" within 24 hours given for the same the earnest money deposited shall stand forfeited. Further such bidder(s) shall not be eligible to participate in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;

12. **The bids offered/ received during the e-auction process shall be provisionally accepted** and the Director shall obtain the orders of Government thereon. No bid shall be regarded as successful bid unless accepted by the Government

13. **After deposit of 10% of the bid amount (as initial bid security) after the conclusion of auction by the highest bidder(s), No request from the highest bidder(s) regarding revocation or the withdrawal of the highest bid shall be considered. In case, any such request is made, the same shall be followed by the Penal action i.e. 10% amount** deposited towards initial bid security shall stand forfeited and un-paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder(s) shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;

14. The earnest money deposited by the bidders other than highest bidders shall be refunded upon completion of the auction proceedings;

15. After the acceptance of highest bid by the State Government and on issuance of Letter of Intent, the LoI holder shall execute a lease deed in Form ML-I appended to the 'Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012' within a period of 90 days of the order of grant of LoI;

16. In case of failure to execute the lease deed, after issuance of acceptance of bid/LoI within prescribed period, the acceptance/LoI shall be deemed to have been revoked and 10% amount deposited towards initial bid security shall stand forfeited and un- paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;

17. After execution of lease deed, either before commencement of the mining operation or before expiry of the period of 12 months from the date of issuance of LoI, whichever is earlier, in case of failure to deposit the balance 15% amount towards security (as required under clause 10(b) above) the acceptance of bid/issuance of LoI/execution of lease deed shall be deemed to have been revoked and 10% amount deposited towards as initial bid security after the conclusion of auction shall stand forfeited. Further un paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;

18. The lessee shall be liable to pay dead rent as determined through open auction or shall pay royalty in respect of each of the minor minerals extracted or removed or consumed by him or his agent, manager, employee etc., whichever is more. The royalty shall be payable at the rates prescribed in First Schedule appended to the State Rules and as may be revised by the State Government from time to time.

19. The lessee shall also deposit/pay an additional amount equal to 10% of the due dead rent alongwith installments towards the '**Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund**';
20. The lessee shall be liable to pay advance Income Tax as per provisions of Section 206 (c) of the Income Tax Act, in addition to the dead rent payable as per term and condition of the lease deed;
21. On enhancement of the annual dead rent with expiry of every three years period, the lessee shall deposit the balance amount of security so as to upscale the security amount equal to 25% of the revised annual dead rent as applicable for one year with respect to the next block of three years;
22. No interest, whatsoever, shall be payable on the security amount deposited under proper security head of the Government;
23. The LoI holder/lessee shall also furnish a solvent surety for a sum equal to the amount of the annual bid for execution of the lease deed. In case the surety offered by the lessee(s) during the subsistence of the lease is not found solvent, the lessee(s) shall offer another solvent surety and a supplementary deed to this effect shall be executed;
24. The mining lessee shall got prepare a Mining Plan along with the Mine Closure Plan (Progressive & Final) from the Recognised Qualified Person as per chapter 10 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012" for mining area granted on lease. The lessee shall not commence mining operations in any area except in accordance with such Mining Plan duly approved by an officer authorized by the Director, Mines & Geology, in this behalf.

Further, the actual mining will be allowed to be commenced only after prior Environmental Clearance is obtained by the LoI holder/lessee for the Mining lease area from Competent Authority as required under notification dated 14/09/2006 issued by the MoE&F, GoI or as amended from time to time.

25. The lessee would also be liable to pay following to the land owners;
 - (a) The annual rent in respect of the land area blocked under the concession but not being operated, and
 - (b) The rent plus compensation in respect of the area used for actual mining operations.

The amount of annual rent and the compensation shall be settled mutually between the landowner and the mining lessee. In case of non-settlement of the rent and compensation, the same shall be decided by the District Collector concerned in accordance with the provisions of Chapter 9 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, and Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012".
26. The total mineral excavated and stacked by the concession holder within the area granted on mining lease shall not exceed two times of the average monthly production as per approved Mining Plan at any point of time;
27. The Mining lessee shall not stock any mineral outside the concession area granted on mining lease, without obtaining a valid mineral dealer license as per provisions contained in Chapter 14 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012";
28. The lessee shall not carry out any mining operations in any reserved/protected forest or any area prohibited by any law in force in India, or prohibited by any authority without obtaining prior permission in writing from such authority or officer authorized in this behalf. In case of refusal of permission by such authority or officer authorized in this behalf, lessee(s) shall not be entitled to claim any relief in payment of dead rent on this account;
29. That no mining operation shall be allowed in the urbansizable zone of area notified by Town and Country Planning Department. Further, in case of the agriculture zone notified by Town and Country Planning Department mining shall be permissible only after obtaining prior permission from the competent authority;
30. A safety margin of two meters (2m) shall be maintained above the ground water table while undertaking mining and no mining operations shall be permissible below this level unless a specific permission is obtained from the competent authority in this behalf;
31. The lessee shall not undertake any mining operations in the area granted on mining lease without obtaining requisite permission from the competent authority as required for undertaking mining operations under relevant laws;
32. In case any lease holder intends to install stone crusher inside lease hold area, the same can be installed as per siting parameters of Environment Department

33. The lessee shall be under obligation to carryout mining in accordance with all other provisions applicable as per Mines Act, 1952, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Forest (Conservation) Act, 1980 and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under Wild Life (Protection) Act, 1972, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

34. Sh. Rajbir Singh has filed a CWP No. 27700 of 2013 before the Hon'ble Punjab and Haryana High Court challenging (i) commencement of lease period after 12 months from the date of acceptance of highest bid/issuance of "**Letter of Intent**" or from date of obtaining of environmental clearance from competent authority which ever is earlier and (ii) payment of rent and compensation to surface right holder/land owners from where mining operations are to be carried out. Therefore, commencement of period of lease & payment of compensation to land owners shall be as per final outcome of court order in said CWP;

35. M/s Om Minerals, one of the LoI holders has filed a CWP No. 7991 of 2014. A few other LoI holders have also filed separate CWPs before the Hon'ble Punjab and Haryana High Court challenging levy of Stamp Duty on execution of 'Lease deed'. The said matter is still pending for adjudication; accordingly, the charging of stamp duty for the execution of lease deed shall be as per outcome of the said CWP's;

36. Further information, if any required, can be had on any working day from the office of the Mining Officer, Mines & Geology Department, Narnaul and Bhiwani or from the O/o the Director General, Mines and Geology, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh.

ARUN KUMAR GUPTA,
Director General, Mines & Geology, Haryana.

Guideline for Online Payments in e-Auction

Post registration, bidder shall proceed for bidding. Bidder shall proceed to select the e-auction he is interested in. On the respective Department's page in the e-auction portal, the Bidder would have following options to make payment for e-Service fee & EMD:

- a. Debit Card
- b. Net Banking
- c. RTGS/NEFT
- d. OTC

Operative Procedures for Bidder Payments

A) Debit Card

The procedure for paying through Debit Card will be as follows:

- (i) Bidder selects Debit Card option in e-Procurement portal.
- (ii) The e-Procurement portal displays the amount and the card charges to be paid by bidder. The portal also displays the total amount to be paid by the bidder.
- (iii) Bidder clicks on “Continue” button.
- (iv) The e-Procurement portal takes the bidder to Debit Card payment gateway screen.
- (v) Bidder enters card credentials and confirms payment.
- (vi) The gateway verifies the credentials and confirms with “successful” or “failure” message, which is confirmed back to e-Procurement portal.
- (vii) The page is automatically routed back to e-Procurement portal.
- (viii) The status of the payment is displayed as “successful” in e-Procurement portal. The e-Procurement portal also generates a receipt for all successful transactions. The bidder can take a print out of the same.
- (ix) The e-Procurement portal allows Bidder to process another payment attempt in case payments are not successful for previous attempt.

B) Net banking

The procedure for paying through Netbanking will be as follows:

- (i) Bidder selects Netbanking option in e-Procurement portal.
- (ii) The e-Procurement portal displays the amount to be paid by bidder.
- (iii) Bidder clicks on “Continue” button.
- (iv) The e-Procurement portal takes the bidder to Netbanking payment gateway screen displaying list of Banks.
- (v) Bidder chooses his / her Bank.
- (vi) The Netbanking gateway redirects Bidder to the Netbanking page of the selected Bank.
- (vii) Bidder enters his account credentials and confirms payment.
- (viii) The Bank verifies the credentials and confirms with “successful” or “failure” message to the Netbanking gateway which is confirmed back to e-Procurement portal.
- (ix) The page is automatically routed back to e-Procurement portal.
- (x) The status of the payment is displayed as “successful” in e-Procurement portal. The e-Procurement portal also generates a receipt for all successful transactions. The bidder can take a print out of the same.

(xi) The e-Procurement portal allows Bidder to process another payment attempt in case payments are not successful for previous attempt.

C) RTGS/ NEFT

The bidder shall have the option to make the EMD payment via RTGS/ NEFT. Using this module, bidder would be able to pay from their existing Bank account through RTGS/NEFT. This would offer a wide reach for more than 90,000 bank branches and would enable the bidder to make the payment from almost any bank branch across India.

- i. Bidder shall log into the client e-procurement portal using user id and password as per existing process and selects the RTGS/NEFT payment option.
- ii. Upon doing so, the e-procurement portal shall generate a pre-filled challan. The challan will have all the details that is required by the bidder to make RTGS-NEFT payment.
- iii. Each challan shall therefore include the following details that will be pre-populated:

Beneficiary account no: (unique alphanumeric code for e-tendering) Beneficiary
IFSC Code:

Amount:

Beneficiary bank branch:

Beneficiary name:

- iv. The Bidder shall be required to take a print of this challan and make the RTGS/NEFT on the basis of the details printed on the challan.
- v. The bidder would remit the funds at latest by 7-8-2015 in advance and make the payment via OTC to the beneficiary account number as mentioned in the challan.
- vi. Post making the payment, the bidder would login to the e-Auction portal and go to the payment page. On clicking the RTGS / NEFT mode of payment, there would be a link for real time validation. On clicking the same, system would do auto validation of the payment made.

List of Net banking banks

1. Allahabad Bank
2. Axis Bank
3. Bank of Bahrain and Kuwait
4. Bank of Baroda
5. Bank of India
6. Bank of Maharashtra
7. Canara Bank
8. City Union Bank
9. Central Bank of India
10. Catholic Syrian Bank
11. Corporation Bank
12. Deutsche Bank
13. Development Credit Bank
14. Dhanlaxmi Bank
15. Federal Bank
16. HDFC Bank
17. ICICI Bank
18. IDBI Bank
19. Indian Bank
20. Indian Overseas Bank
21. Indusind Bank
22. ING Vysya Bank

- 23. J and K Bank
- 24. Karnataka Bank
- 25. Kotak Mahindra Bank
- 26. Karur Vysys Bank
- 27. Punjab National Bank
- 28. Oriental Bank of Commerce
- 29. South Indian Bank
- 30. Standard Chartered Bank
- 31. State Bank of Bikaner and Jaipur
- 32. State Bank of Hyderabad
- 33. State Bank of India
- 34. State Bank of Mysore
- 35. State Bank of Travancore
- 36. State Bank of Patiala
- 37. Tamilnad Mercantile Bank
- 38. Union Bank of India
- 39. United Bank of India
- 40. Vijaya Bank
- 41. Yes Bank

D) OTC

The bidder shall have the option to make the EMD payment via OTC. Using this module, bidder would be able to pay from their existing ICICI Bank account through CASH/DD/ICICI BANK CHEQUE.

- i. Bidder shall log into the client e-procurement portal using user id and password as per existing process and selects the OTC payment option.
- ii. Upon doing so, the e-procurement portal shall generate a pre-filled challan. The challan will have all the details that is required by the bidder to make OTC payment.
- iii. Each challan shall therefore include the following details that will be pre-populated:

Beneficiary account No.(unique alphanumeric code for e-tendering) Beneficiary
IFSC Code:
Amount:
Beneficiary Bank Branch:
Beneficiary name:

- iv. The Bidder shall be required to take a print of this challan and make the OTC on the basis of the details printed on the challan.
- v. The bidder would remit the funds at latest by 7-8-2015 in advance and make the payment via OTC to the beneficiary account number as mentioned in the challan.

For making payment through Demand Draft against the online Challan generated for OTC:

If the amount is more than 50,000 (Fifty Thousand) then the intended bidders are required to provide ICICI Bank cheque or draw demand draft in favour of below furnished details:-

Sr No.	Account Name/ title	Account No.
1	GOH E- PROC EMD ESCROW A/C DSND - MINGEO	001305010048

Instructions for Intending Bidders to participate in Auction

How to Participate:

Part A

E-Auction Portal Signup & Bidding Process

Web portal for e-Auction of Haryana Single e-Procurement portal at <https://haryanaeprocurement.gov.in>

1. Signup: Bidder must required to create a login ID and password on the e-Procurement Portal by providing the basic information. Signup on the portal is free. Bidder has to create the login account for participating online into e- auction.

After filling up all the required details carefully, bidder has to click on submit button in order to complete the Sign-up process.

On completion of the Sign-up process, bidder will receive a registration activation mail on the registered email ID.

Contractor Registration Form

First Name *	Kanwarjeet
Last Name *	Singh
Company Name *	Nex
Username *	testbidder6
Password *	*****
Confirm Password *	*****
Security Question *	Cop
Security Answers *	Sheriff
Discipline *	Auction
Email *	testbidder6@gmail.com
Secondary Email	:kunwarjeetsingh@hotmail.co
PAN *	CZDPS0707E
Telephone *	01722582009
Fax	01722582008
Mobile	9592259876
City *	Panchkula

State *	Haryana
Country *	India
Vendor Category *	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;" type="button" value="NSIC"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; margin-top: 5px;"> <p>-Select Vendor Category-</p> <p>NSIC</p> <p>SSI</p> <p>OPEN</p> <p>EMD Exempted</p> <p>Partial EMD Exempted</p> </div>
Company Office Address *	SCO No. 9, Sector 16, 2nd Floor www

Register for Portals *	<input type="checkbox"/> HSIIDC <input type="checkbox"/> HVPNL <input type="checkbox"/> HSRDC <input type="checkbox"/> DAKSHIN HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED <input type="checkbox"/> UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED <input type="checkbox"/> POWER GENERATION CORPORATION LIMITED <input type="checkbox"/> ROADWAYS ENGINEERING CORPORATION <input type="checkbox"/> HARYANA TRANSPORT DEPARTMENT <input type="checkbox"/> DSND
------------------------	---

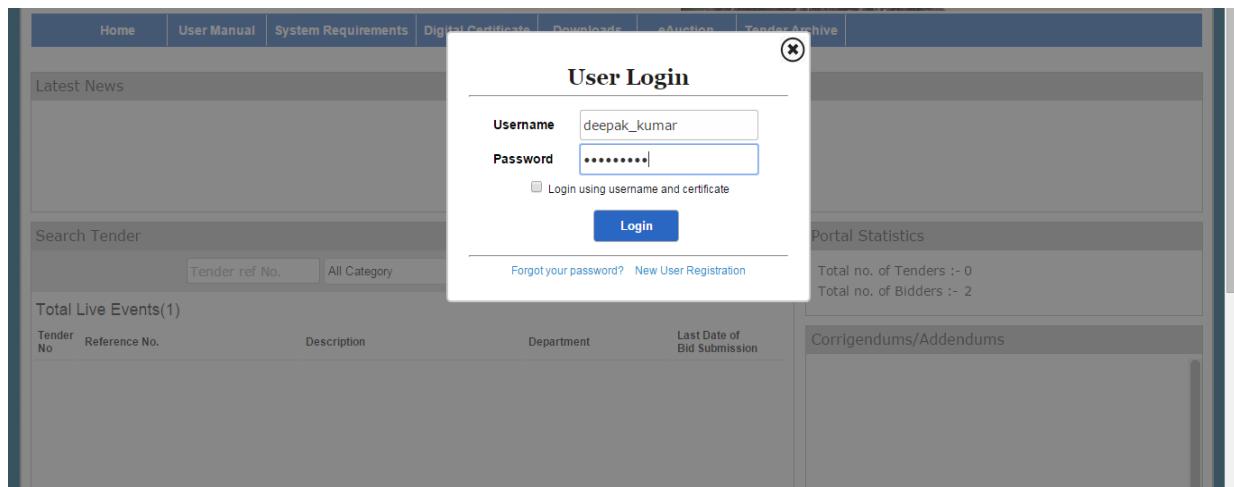
Drag to order					
1	2	3	4	5	6

Note: (a) In case of Individual the bidder must enter his/her name or mention Individual against company Name.

(b) For vendor Category select 'OPEN' from the drop-down.

2. **Search Auction:** Bidder can view the live auction events and download the related documents without login to the portal.

3. **Bidder Login:** Login to the eAuction portal for online participation on Auction event. Interested bidders have to enter their online registered login ID and password with the portal. If the bidder forgets his/her password, the same can be retrieved by clicking on the "forget your password" link at the website, and thereby furnish their registered security question and answer to recover password at the e-Auction website. After receiving the correct security question and answer, bidder will receive auto-generated email from the system containing the password reset link.



4. **Dashboard:** After successful login, bidder will be redirected to the dashboard. Dashboard is divided into 2 Sections.

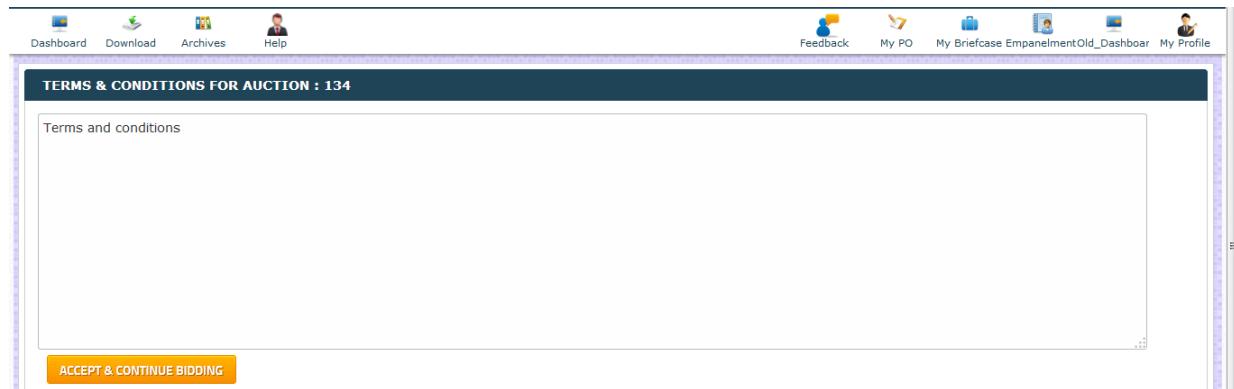
- a. **Current Events:** Current events will display the live auctions. Bidder can be able to participate in any of the live auction as per the scheduled date and time.
- b. **Completed Events:** Once the auction will be concluded, it will be shown in this section. Current event tab. Bidder can check for the reports in this section after the auction will be concluded.

Bidder has to click on "Bid Here" link in order to bid on the auction he/she wish to participate.

EVENT MANAGEMENT							
Current Event(s)				Completed Event(s)			
ID	Tender Reference No.	Start Time	End Time	Check Task	View Bid	Bid Here	Post Query
134	Auction of Plots 19.12.2014-1	2014-12-19 11:37:00	2014-12-23 23:59:00				

EVENT MANAGEMENT							
Current Event(s)				Completed Event(s)			
ID	Tender Reference No.	Start Time	End Time	Reports	Post Query		
Record not found.							

5. **Acceptance of terms and conditions:** Bidder has to read carefully & accept the auction terms and conditions before bidding online on the e-Auction portal. And the bidder will be redirected to the e-Payment page.

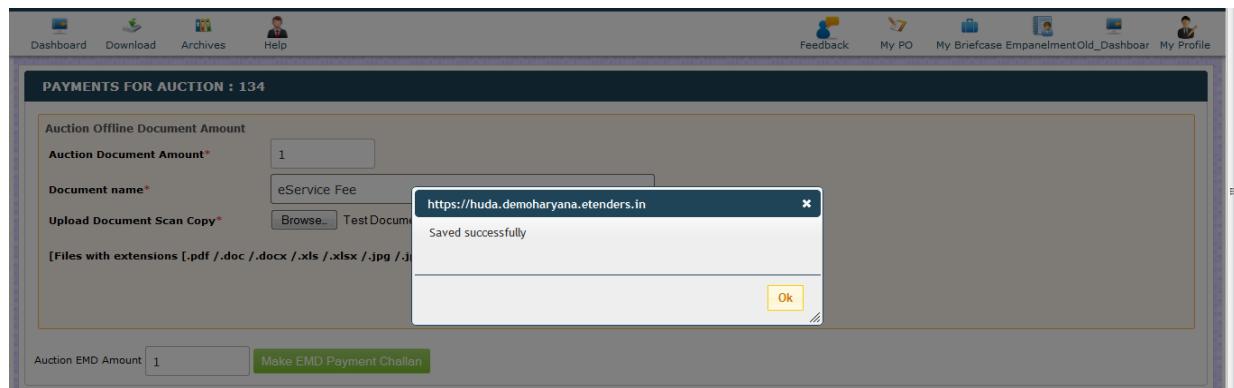


6. **Online payment for eService and EMD/ Registration fee:** Bidder is mandatorily required to pay eService fee of Rs. 1000/- using the online payment gateway through their Debit Card/Internet Banking.

For EMD/Registration fee payment bidders can have the option to make online payment of the amount through Debit Card/Internet Banking/RTGS/NEFT/OTC.

To make payment through RTGS/NEFT/OTC a pre-filled Challan shall be generated at the e-Auction portal for EMD/Registration fee payment. And remit the funds at least T+1 working day in advance to the closing date of e-Bidding.

So therefore all the intending bidders are require submitting of their EMD / Registration fee amount well in advance keeping in view the closing date & time of the e-Auction event / Online Registration.



NATIONAL ELECTRONIC FUND TRANSFER (NEFT)/REAL TIME GROSS SETTLEMENT(RTGS)
(To be filled by Application in BLOCK LETTERS)

Bank's Copy

Part-1[Details of applicant/remitter/orignator] Date 2014-12-19 12:47:25

Refund Account Name: kanwarjeet Singh
Refund Account No.: 1234567890
Refund Account Bank IFSC Code: PUNB00012345

Details of Beneficiary

Bank:- ICICI Bank Ltd
Branch:- ICICI Bank Ltd CMS, Mumbai.
Beneficiary Name:- 123
Beneficiary A/C No.:- 123134207
Beneficiary IFSC:- ICIC0000104
Type of A/C:- CURRENT
Amount Rs.:- 1.00
Order Id:- E-123134207

Disclaimer:

- It is advised that all bidder make payment via RTGS/NEFT atleast one day in advance to the last day. In the event bidder making payment on the last day and same is not available for the bidder for validation on account of any reason whatsoever, Department, its banker, or e-procurement service provider or payment gateway service provider would not be held responsible in any manner. In such cases bidder may not be able to submit the tender.
- It is the bidder's responsibility to ensure that RTGS/NEFT payments are made to the exact details as mentioned in the challan. In the event of any discrepancy, payment would not be considered and would not be available for validation of EMD payment.

7. **Auction Bidding:** Once the e- challan generated by respective bidder is verified by the system, he/she can enter into the online auction hall by clicking on the button "Go for Auction Bid".

PAYMENTS FOR AUCTION : 134

Auction Document Amount Rs. 1 successfully paid

Make EMD Payment Challan

Go for Auction Bid

On the bidding page, bidder is required to bid on the auction. Bidder can check for the Auction Documents/attachments in the real time. Page can also have a view to see the time remaining in the auction bidding.

ITEM(S) OF AUCTION

Auction started

Auction ID: 134 **Auction Starts:** 2014-12-19 11:37:00 **Auction Ends:** 2014-12-23 23:59:00

Time Remaining: 4 Days 11 Hours 3 Minutes 55 Seconds **Status:** Started **No of extension:** 0

Item Name	Opening Price	Last Bid	Bid Price	Operation
AUCTION AD DAUSA RESIDENTIAL SCHEME, CE - JYOTI NAGAR, JAIPUR	200000.00 Lacs			<input type="text" value="Price"/> Rs. <input type="button" value="Place Bid"/> Next bid price: 200002.00 Thousands Bid Inc.: 2.00 Thousands Reserve Price: 200000.00 Lacs Max. Inc. Per Bid: 5
Full View				
PDF				

Part B

Closing

The auction remains live till the closing date and time as defined in the bid document. Bidders can see the closing date and time by accessing the auction document and even on the e-Auction portal. However, the time of e-Auction will automatically be extended if the bidder tries to bid in the last 5 minutes before the closing time of the auction for the next 5 minutes. However, the increment during extended period will be multiple of 100000 (one lakh) instead of 50,000 (fifty thousand).

E-Payment for Bid Security Amount by the H1 Bidder.

The highest bidder has to initiate online payment towards 'Bid Security' under the stipulated time frame as referred to the event Document. The concern bidder require to follow the below given screenshot for making payment online through RTGS/NEFT/OTC to the beneficiary account number pre-filled generated under the e-challan. The aforesaid bidder must remit the fund in due course of time.

Current Events

ID	Tender Reference No.	Start Time	End Time	Bid Here
546	KMPE/02/2015	2015-03-10 18:14:00	2015-03-20 12:00:00	
514	ICB for Development of 6 lane Kundli-Manesar-Palwal Expressway	2015-02-22 22:42:00	2015-03-20 12:00:00	

Completed Bid

ID	Tender Ref. No.	Rework Bid	View Bid	Start Time	End Time
Record not found.					

Opening Pending

ID	Tender Ref. No.	Start Time	End Time	Operations
Record not found.				

Opened / Awarded

ID	Tender Ref. No.	Start Time	End Time	Reports	Post Query
594	Auction of Booth_2014/2015_TEST	2015-03-02 19:00:00	2015-03-05 12:00:00		Bid Security
595	Test Auction (DO NOT BID)	2015-03-02 19:10:00	2015-03-03 20:09:47		Bid Security
602	Test Auction please do not bid in this	2015-03-03 19:00:00	2015-03-03 19:15:00		Bid Security

BID SECURITY FOR AUCTION 594

Auction Details

Auction ID:	594	Auction ref No:	Auction of Booth_2014/2015_TEST
Auction Starts Date:	2015-03-02 19:00:00	Auction Ends Date:	2015-03-05 12:00:00
Auction Type	F Auction		
Auction Type	Limited Auction	Auction bid security %	10

Auction item Details

You are H1 Bidder for this item

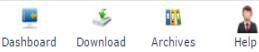
Item name: Auction of Booth No. 1 **Your Bid is:** 9 [Pay Bid Security Payment](#)

You are H1 Bidder for this item

Item name: Auction of Booth No. 2 **Your Bid is:** 9 [Pay Bid Security Payment](#)

You are H1 Bidder for this item

Item name: Auction of Booth No. 3 **Your Bid is:** 8 [Pay Bid Security Payment](#)





Refund EMD Account Information

Refund Account Name	ABCV
Refund Account Number	123456788
Refund Account Bank IFSC Code	PNB01710

Proceed

[Print Challan](#)

NATIONAL ELECTRONIC FUND TRANSFER (NEFT)/REAL TIME GROSS SETTLEMENT(RTGS)
(To be filed by Application in BLOCK LETTERS)

Bank's Copy	
Part-1 [Details of applicant/remitter/orignator]	Date 2015-03-14 11:08:23
Refund Account Name	ABCV
Refund Account No.:	123456788
Refund Account Bank IFSC Code	PNB01710
Details of Beneficiary	
Bank:-	ICICI Bank Ltd
Branch:-	ICICI Bank Ltd CMS, Mumbai.
Beneficiary Name:-	HSII
Beneficiary A/C No.:-	HSII59411727
Beneficiary IFSC:-	ICIC0000104
Type of A/C:-	CURRENT
Amount Rs.:-	0.90
Order Id:-	AU-SEC-HSII59411727
Disclaimer:	
1. It is advised that all bidder make payment via RTGS/NEFT atleast one day in advance to the last day. In the event bidder making payment on the last day and same is not available for the bidder for validation on account of any reason whatsoever, Department, its banker,or e-procurement service provider or payment gateway service provider would not be held responsible in any manner. In such cases bidder may not be able to submit the tender.	
2. It is the bidder's responsibility to ensure that RTGS/NEFT payments are made to the exact details as mentioned in the challan. In the event of any discrepancy, payment would not be considered and would not be available for validation of EMD payment.	
3. Bidder is required to generate challan for every tender since details in the challan are unique to the tender and bidder combination. Bidder is not supposed to use challan generated in one tender for payment against another tender.	
4. Under no circumstance, including whether the bidder has made duplicate/incorrect payments or correct payments not validated by the bidder for which tender validity has expired, Department or its Banker or its service providers are under no obligation to disclose the details of payment made by any bidder.	
Remit the amount as per above details, by debiting my/our account for the amount of remittance plus Bank charges.	
Customer's Signature	
Contact Phone No :	

Verification

Designed & Maintained By **Nextenders India Pvt. Ltd.**

Copyright © 2014 Government of Haryana eProcurement | Powered by **Nextenders**

Note- A training-cum-orientation program for the intending bidders will be held on **25.07.2015 and 01.08.2015 at Chandigarh office of Nextenders from 12.00 noon to 1.00 P.M.** Parties interested in attending the same are requested to contact/confirm participation to Sh. Kanwarjeet Singh Mobile 09592259876, Sh. Sat Dev Sharma 9872252144 Sh. Deepak Mobile – 9501176347 or the helpdesk on Toll Free No. 1800-180-2097 and 0172-2582008/2582009/2618292 or through E-mail: chandigarh@nextenders.com.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 11/6/2015-4 श्रम— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स फूजीतसू टेन, प्लाट नं 383, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर फेज-II, सेक्टर-3, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं: 7-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्:—

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच कारखाने में काम करने से इन्कार करती है, उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापिस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएंगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये कैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेंगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापिस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में बुलाया जाता है।
10. कारखाना केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्यायनिर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिलाओं कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके योन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2015

No. 11/6/2015-4Lab.- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of **M/s Fujitsu Ten Plot No. 383, Industrial, Growth Center Phase-II, Sector-3, Bawal, District Rewari, Haryana**, so as to authorize the employment of women workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.

3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan *vide* judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 13/22/2015-4श्रम- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स एपीपी (ईपीडीया) पेपर प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं 0 122-बी, सेक्टर-6, बावल, आईजीसी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं: 7-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके अर्थात्:—

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा न ही उसे अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापिस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्द्रीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।

11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्यायनिर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

अनुराग रस्तोगी,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2015

No. 13/22/2015-4Lab.- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of **M/s APP (INDIA) Paper Private Limited Plot No. 122-B, Sector-6, Bawal, IGC, District Rewari, Haryana** so as to authorize the employment of women workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the woman workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan vide judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

ANURAG RASTOGI,

Principal Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 11/17/2015-4श्रम- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स मन एण्ड हुमेल फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं 19, फेस-II, सेक्टर-5, बावल इण्डस्ट्रियल ग्रौथ सेन्टर, बावल, रेवाड़ी, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं: 7-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके अर्थातः-

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो साथं 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापिस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये कैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्द्रीय में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सके।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th July, 2015

No. 11/17/2015-4Lab.- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of **M/s Mann and Hummel Filter Private Limited Plot No. 19, Phase-II, Sector-5 Bawal Industrial Growth Center Bawal, Rewari, Haryana** so as to authorize the employment of women workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.

9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan *vide* judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2015

संख्या 11/6/2015-4श्रम — कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स पानीपत रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स (रिफाइनरीज डिविजन), पानीपत, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं 7-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्:—

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये कैच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदल दी जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापिस ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में बुलाया जाता है।
10. कारखाना की कैंटीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सकें।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) के निर्देश के निबन्धन के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**LABOUR DEPARTMENT****Notification**

The 17th July, 2015

No. 11/6/2015-4 Lab.- In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of **M/s Panipat Refinery and Petrochemical Complex (Refineries Division) Panipat, Haryana**, so as to authorize the employment of women workers in two shifts between the hours of 7.00 p.m. to 10.00 p.m. for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely:-

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 p.m. to 10.00 p.m. shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to women workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others Vs State of Rajasthan *vide* judgment dated the 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.